मिल रहा है। इससे पूरे इलाके में असंतोष व्याप्त है। मैं स्वयं चार-पांच रोज पहले वहां थी। मैं उसी इलाके से आता हूं। मेरा निवेदन कि इस चन्द्र कूप में पानी की व्यवस्था की जाय जिससे श्रद्धालु भक्त लोग जल चढ़ा सकें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि वहां पर देवघर शहर में पिछले 20–25 रोज से बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हैं। संलग्न अखबार मेरे पास है। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इसको पढ़कर सुनाऊं। 25 दिनों से इस शहर में बिजली नहीं है। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर देशी और विदेशी यात्री आते हैं, इसलिए तुरन्त जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था की जाये और चन्द्र कूप में पानी की व्यस्था की जाये जिससे तीर्थ-यात्रियों में क्षोभ समाप्त हो।

STATEMENT BY MINISTER—

Grant of Financial Assistance in case of deaths due to cyclone in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now we take up the statement by the Minister of State for Rural Development.

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा): महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में हाल ही में आए चक्रवात के कारण मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में सदन की आज्ञा से एक वक्तव्य देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने कल इस आपदा के कारण हुई कुछ मौतों के बारे में सदन में एक वक्तव्य दिया था। हमारे पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 72 व्यक्ति मरे हैं, सात व्यक्ति तमिलनाडु में और 2 पांडिचेरी में मरे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए उप-प्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्री ने मौत के प्रत्येक मामले में इंडियन पीपल्स नेचुरल कैलेमिटीज ट्रस्ट से 25,000 रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है।

मैं एक बार फिर से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और प्रभावित राज्य सरकारों को जब भी और जैसी भी जरूरत होगी, सभी संभव सहायता मुहैया करायी जाएगी।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने कहा है कि आन्ध्र प्रदेश में बड़ा भयंकर तूफान आया जिसका असर दूसरे सूबों पर भी हुआ है। इसमें सरकार ने कहा है कि 72 आदमी मरे है लेकिन अखबारों में जो खबर छपी है उसमें 72 से कहीं ज्यादा लोग मारे गये बताये गये हैं। सन् 1977 में इसी तरह का तूफान आंध्र प्रदेश में आया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार के सामने 1977 की मिसाल थी। जो तूफान की रफ्तार 1977 में थी वही आज के तूफान की भी थी। तो सरकार ने, जो मौसम विभाग ने उनको सूचना दी उसके मुताबिक कुछ प्रीकाशंस लिये जो कि बहुत कमजोर थे, पिछड़े थे और देर से लिये गये थे। इसके साथ-साथ जब तूफान आया, जब पहले दौर का तूफान आया तो उसके बाद कुछ शांति आ गई। शांति के वक्त केन्द्रीय सरकार का जो मौसम विभाग था, उसने इस मामले में ढिलाई बरती और फिर कोई वार्निंग नहीं दी। मान्यवर, इसमें कहा गया है कि 25 हजार रुपया दिया गया है। यह धनराशि बहुत कम है, वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इतनी कम रकम से उनका घर-बार कसे बन जायेगा, इस रकम से कैसे उनका घर आबाद हो जाएगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आमतौर पर जो घर बरबाद हुए हैं, डिवास्टेटेड हुए हैं तो वह किन लोगों के हुए हैं? मछली पकड़ने वाले मछुआरों के हुए हैं, या खेतीहर मजदूरों के हुए हैं या बड़े बड़े घर इससे बरबाद हुए हैं?

[चौधरी हरि सिंह]

दूसरी बात यह है कि उनके बच्चे वहां भूख से बिलख रहे हैं, वे भूख से मर रहे हैं उनके पास खाने के लिये कुछ नहीं है, उनके पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं, वे बाहर पड़े हुए हैं, ऐसी हालत में केन्द्रीय सरकार ने उनको कितनी धनराशि दी है। जो धनराशि उनको दी गई है उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। सरकार ने जो धनराशि दी है तो क्या उसको बांटने की भी समुचित व्यवस्था की गई है? यह देखने में आया है कि केन्द्रीय सरकार अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो जनता पार्टी या जनमोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इसको बांटने का काम कर रही है और वे लोग इसमें भेदभाव कर रहे हैं। यह अन्याय है, यह उचित नहीं है। इसमें पार्टी लाइन को भुलाकर काम किया जाना चाहिए। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने बड़े पैमाने पर वहां पर कितने बूथ, कितने सप्लाई सेंटर खोले हैं, वहां पर दवायें कितनी तादाद में पहुंची हैं, वहां पर कितना चावल दिया जा रहा है और इसके लिये कितने डिपो, कितने सेंटर खोले हुए हैं और कितने आदमी इस काम में लगे हुए हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, I am on a point of order. The Minister's statement says about a trust. Whom does this trust belong to? How can the Government make distribution out of a trust? How can the Government make a statement that out of the money of the trust, it is going to distribute? Is it a Government trust or a Government fund? If through somebody's trust money is distributed by some Minister, why should the Government come on the floor of the House and inform aboot the formation of the trust? I want your ruling on this. Kindly go through the Statement. This Rs. 25,000 is through the Indian People's Natural Calamities Trust.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Iti is over and above.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Why should it come to the House? The House cannot be taken like this. (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): I am on a point of order.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: With all sympathies to those brethren who have suffered, the Government had come out with a fabulous amount of money yesterday. I am only concerned about the procedure of the House. What is this Trust? What is the purpose of the Trust? Who are the Members of the Trust? What is the money that is being given? Why should the Government make use of Parliament to announce this help from a Trust? After all the Government should come out with its funds. If I have a trust and I am giving money, why should the Government make a statement on the floor of the House? I want a ruling on this before going to the clarifications.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: On the same thing I want to say. Apart form the name of the trust there is no other information at all in the Statement. Therefore, what is the point of this statement? I was going to raise that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Your name is there in the list. Your name is also there. You can raise this question at that time. So far as the point of order is concerned that does not stand because the Government has every hight to make a statement. If you feel that there is some discrepancy in the statement, then while seeking... (*Interruptions*) Just a minute. Let me give my ruling on the point raised by the hon. Member.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): It is related to that. Does the Government also have the right to conceal information? If the Government is also spending out of its own funds for relief, why is that information missing from here?

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Yesterday it was given.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Does the Government have the right to promote the identity and publicity of a particular private or public trust in the name of calamitous relief? I am seeking your ruling on that. Can the time of the House be taken for the benefit of publicity of a particular Trust?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Honourable Members must kindly understand that the Government has the right to make a statement on the floor of the House. If you have any point to be questioned in relation to that you are all entitled to do that. Therefore, let us please proceed with the programme.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: My point is that the Government is free to make a statement. I have no objection. If the Government is spending money from the Consolidated Fund, we have no objection. There is the Prime Minister's relief fund, drought fund, this fund and that fund. But can the Government hold a brief for some other Trust created by somebody? And the Government is not clear about it. This calamities Trust has been created by somebody else. We do not know who are the Trustees. Can this House be used for the benefit of a particular Trust?

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): You first disclose the name of the Chairman of the Trust and members of the Trust. Then only we will allow this statement to continue and then only we will seek clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The Minister will clear the point which you have raised just now. Then we will proceed with seeking clarifications.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: I want to raise a point of order... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Let the Minister reply.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Several Members have requested that all agencies should be involved to render help to the cyclone victims. I hope the Minister will come out with details.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The hon. Member will be given an opportunity.

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Sir, I am on a point of order. The hon. Minister has referred to a statement which he made yesterday. As the entire world is aware—I use this with great caution—not just this House or Mr. Vice-Chairman or the Minister—that this side of the House, the Congress party was not present in the House yesterday because we were sitting on a fast yesterday and we were not here. It is obvious there is some thing which we have no knowledge of. So rather than take resort to cleverness by saying, "I will reply to this at the end when the Members seek clarifications," I think the Minister must get up and he must clarify now... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The Minister volunteered to give some more information. Let the Minister reply.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, ऐसा लगता है कि कल मैंने जो वक्तव्य दिया और जो समाचार पत्रों में भी आया है उस ओर कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया है। मैंने उस में स्पष्ट किया है कि तीनों राज्य सरकारों को कितनी राशि खर्च करने के लिये दी गई है । जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि अखबारों में यह आया है और रेडियो में दूसरा समाचार आया है मरने वालों के बारे में, तो मैं यह कहना चाहता हूं.. **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप बात समझे नहीं है । यह बताइये इंडियन पीपल नेचूरल कैलेमिटीज ट्रस्ट के चेयरमैन कौन हैं **(व्यवधान)**

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : पूरी बात कहने दीजिये

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Hon'ble Minister, the point raised by the Member is regarding the Trust. Some more informa-

[Shri M. A. Baby]

tion they require regarding the compensation, nature and character of the Trust. Please explain that. (*Interruptions*).

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Sir, is it appropriate to bring the Trust in this information?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Once that is explained, all of us will understand whether that is appropriate or not.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, ट्रस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए सूचना चाहिए लेकिन मैं . . . (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह कैसे आप कह रहे हैं . . . (व्यवधान) इस ट्रस्ट का मालिक कोई स्मगलर है, और चोर है, डकैत है, देशद्रोही है, कौन है यह हमको बतायें . . . (व्यवधान) इस ट्रस्ट का मालिक कौन है . . . (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने कहा कि विस्तार के साथ यदि जानना चाहते हैं तो पहले से सूचना चाहिए . . . (व्यवधान) मैं आपको बताता हूं . . . (व्यवधान)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Sir, I am on a point of order. I take very strong exception and I would like to say that the Minister is misleading this House and I will make it clear. In yesterday's statement, according to the revised para 7 the hon. Minister has said, "according to the revised scheme for financing the relief expenditure which came into force from 1-4-90"... it was not disclosed to Parliament—that on 14,00 based on the recommendations of the Ninth Finance Commission, the State Government of Andhra Pradesh and Tamil Nadu have been allocated Rs. 86 crores and Rs. 39 crores respectively under the "Calamity Relief Fund". It is called the "Calamity Relief Fund". Then, in the same paragraph, it goes on to say, "in case any State Government has ways and means problem, it can approach the Ministry of Finance for release of ways and means advance which can be later adjusted against the "Calamity Relief Fund" and when it becomes operative..."—Fund and not Trust. And today's statement refers to the "Indian Peoples Natural Calamities Trust". I would like to mention that we have at the moment the Prime Minister's Relief Fund. It is a fund and it is not a Trust and we have other funds also at the discretion of the Governor, at the discretion of the President. But this is the first time that I have been a reference and it is quite clear, the money has gone from the fund which is a constitutional body to a Trust which is an unconstitutional body and I would like to know from the hon. Minister why this has happened. What is this Trust? Who is the owner of this Trust? Please explain to us immediately. (*Interruptions*). I suggest discussion ...(*Interruptions*)... I would like to know from the hon. Minister why his Ministry has not disclosed to Parliament such a vital information as the formation of this fund on 1-4-90. It was not disclosed to Parliament. I would also like to know what is the relationship between the fund and the Trust. (*Interruptions*).

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): We can quite appreciate the anxiety the hon. Member has... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I have permitted him.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Yesterday, we have sought clarifications...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A BABY): I have permitted him to speak as I have permitted you to speak. (*Interruptions*).

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Mr. Vice-Chairman, let it not be said that I am not disciplined. (*Interruptions*)... hear the hon. Member.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Mr. Vice-Chairman, I have not yielded. (*Interruptions*). As I was telling, I can quite appreciate the anxiety of the hon. Members because they are absolutely concerned about our bro-

thers who are suffering in the southern region and it is quite appreciated. But since they were not in the House yesterday, I would just like to make a mention that some of the hon. Members raised a point whether in addition to whatever the hon. Minister has declared, any more funds were made available to this particular region affected. So, in addition to the clarification sought, I think the hon. Minister is just replying to that. Now, the second Question is about what the Trust is, why it is there and who the Chairman is. I think that is absolutely the second part of it. Thank you. (*Interruptions*).

SHRI S. S. AHLUWALIA: That is the first part of it. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): One minute. Let me just tell the Government and the hon. Minister present here that the hon. Members from this side raised the point that yesterday it was announced that assistance has been extended from the fund and today in the first paragraph of the statement, reference has been made to the Indian People's Natural Calamities Trust. So Members are asking what the relationship between these two is and what the differences are and what the composition, character and contents of this particular trust are and how the Government of India is associated with this trust. These are certain pertinent questions. You please explain.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : महोदय, मैंने जो कल राहत कोष की बात कही थी, उसके अलावा यह ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट से पैसे देने की बात है।

यह पैसा सिर्फ मृतकों के परिवारों को मिलेगा। इस ट्रस्ट का चेयरमैन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है और यह ट्रस्ट 1900 ई. में कायम हुआ था।

इस ट्रस्ट के जो पहले डोनर थे, वह जयपुर के महाराजा थे, जिन्होंने 15 लाख रुपये दिया और वह जमा रहा। उस ट्रस्ट का चेयरमैन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता रहा है। जब जरूरत होती है ऐसी आपदाओं के लिए, तो ट्रस्ट से पैसा निकाल कर दिया जाता है। अब यह विस्तार के साथ जानना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से सूचना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यह ट्रस्ट 1900 ई. से चालू है और इस ट्रस्ट का चेयरमैन भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं और इस ट्रस्ट की शुरुआत जयपुर महाराज ने 15 लाख रुपये देकर की थी।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I have only one problem, Mr. Vice-Chiarman. I have heard the hon. Minister with great attention. His officials are present in the gallery. I agree it is very much possible and probable and very likely that the hon. Minister does not have this information. But I am sure he can get it within seconds by just writing a small chit.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैं पहले ही कह रहा था। आप सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं। . . (*व्यवधान*)

SHRI VISHVJIT P. SINGH: What is the present composition of the trust? I do not deny that the Agriculture Minister must be the Chair man. But how is this trust managed? We would like to know this thing.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने कहा ना कि यदि विस्तार से जानना चाहते हैं, तो अलग से सूचना चाहिए। मैंने संक्षेप में आपको सूचना दी है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Hon. Members, the anxiety of a section of Members from this side is quite understood. That is why I have specifically asked the Minister to explain why this discrepancy is there. Now, whatever information the Minister is in possession of has been shared. It would have been better if more of information was available. I hope later on the Government will come forward with more information. Both sides are equally concerned about the cyclone and the situation there. Let us now go ahead with the seeking of clarifications.

[Shri M. A Baby]

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Vice-Chairman, I am again on propriety. Can the funds distribution of any trust—the Minister may be its Chairman or it may be under a Ministry—be made through Parliament? Can the floor of this Parliament be used by the Government for announcing this kind of thing? I want a specific ruling on this. If tomorrow a Minister heading a trust, may be a genuine trust, announces something—outside Parliament he can do it—can he make use of the forum of Parliament for such an announcement? ...(*Interruptions*)...

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Sir, I am only on the question of propriety. Soon we will have the Law Minister giving us information about the money being given to the refugees from Jammu by the Indian Express Trust. That is what we are going to have very soon.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The point is that even the Prime Minister's Relief Fund is not a Government fund. It is not a Government fund. That is the information. Therefore, some information regarding the aid that has been rushed to the victims is being given by the Government. ..(*Interruptions*)...

SHRI VISHVJIT P. SINGH: May I make it clear, Sir? It is not a Government fund. It is a Government-administered fund. There is a vast difference between these two...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): You cannot say that the Prime Minister's Relief Fund is not a Government fund. Any fund which is audited is a Government Fund... (*Interruptions*)... And if any fund is not audited, that is not a Government fund. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. M. JACOB (Kerala): The Trust's composition is always important when it is announced on the floor of Parliament because the Trust can consist of people whose antecedents are suspect. Such things cannot be anticipated by Parliament. Using the name of a Minister to be the Chairman cannot be an excuse for the reality of a trust, of the sincerity of a trust or the desirability of a trust to be acceptable to Parliament. So the Prime Minister's Relief Fund cannot be compared with anything because the Prime Minister's Fund is a Prime Minister's Fund. There are no participants. Shareholders are not there. The Prime Minister, in the capacity of Prime Minister, created a Relief Fund, and all the State Governments and individuals donate to that Fund.

SHRI DIGVIJAY SINGH: The Agriculture Minister is ex-officio Chairman of the Fund. ..(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, a point has been made...(*Interruptions*)...

SHRI VISHVJIT P. SINGH:: May I share one piece of information with you, Sir? My family runs various charitable trusts and we have also people in public life who are ex-officio Chairman by virtue of their position or ex-officio Chairman of our trusts. It does not mean that it comes to Parliament and we take the sanctity of Parliament to distribute the money...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Your point has been noted down. The point has been raised sufficiently. Let us not waste more time on this...(*Interruptions*)...

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Vice-Chairman, the issue is whether the Government accepts that it was an error of judgement which has brought one particular trust as a part of the Government's statement on relief in calamities. And two, in future, will such a lack of discretion be avoided? If such trusts are going to come, let us have a total list of trusts, how they are operating and why they are

given only in this case and why money is not released in other cases. There are several other issues which come up.

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : मान्यवर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहां मिनिस्टर ने अभी जो स्टेटमेंट किया है, कल भी स्टेटमेंट किया था इस हाऊस में, हमारे मैंबरान यहां हाजिर नहीं थे . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): That is a different matter. ...(*Interruptions*)...

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : मेरी बात तो सुनिए । वहां जो आन्ध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में जो कुछ लोग मरे हैं उनको जो हम रिलीफ देने जा रहे हैं उसमें कुछ ज्यादा दे सकें उस की बात . . **(व्यवधान)** यह बात हम करें . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): That is a different matter. Hon. Member, that can be raised separately. That is a clarification. Please sit down...(*Interruptions*)... Please sit down.

श्री अनंतराय देवशंकर दवे : आप सुनिए, आप लोग क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं वह मिनिस्टर साहब देने के लिए भी तैयार हो गए हैं, जितनी इन्फर्मेशन चाहिए वह . . . **(व्यवधान)** . . आज जो हम बात कर रहे हैं, जो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं उसके मुताबिक हम कितनी ज्यादा मदद वहां लोगों को पहुंचा सकें तो वही बात करें तो हमारे सब के लिए ठीक है । . . **(व्यवधान)**

SHRI M. M. JACOB: Sir, I have one request to make to the Government through you to make sure that the money of the Trust is white money.... (Interruptions)... and it is legal money and not black money... (Interruptions)... which is involved in the Trust and which is brought before Parliament.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि आज आप एक नया नियम या एक रास्ता खोल दे रहे हैं । आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट काम कर रहे हैं । आज सिर्फ एक ट्रस्ट का नाम लिया जा रहा है । क्या आप इंकार कर सकते हैं कि "भारत सेवक समाज" वहां पर लंगर नहीं चला रहा है ? क्या आप अस्वीकार कर सकते हैं कि रेडक्रास वहां मदद नहीं कर रहा है ? क्या आप अस्वीकार कर सकते हैं कि अरविंद आश्रम के लोग वहां काम नहीं कर रहे हैं । अगर उनकी बात नहीं कर सकते तो एक ट्रस्ट की बात क्यों कहते हैं और उस को पापुलराइज़ करने के लिए आप पार्लियामेंट . . . **(व्यवधान)** . . . मिसयूज क्यों कर रहे हैं ? You give a ruling on this...(*Interruptions*)...

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: You cannot compare this Trust with other trusts...(*Interruptions*)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, you give a ruling on this...(*Interruptions*)...You are opening a wrong gate...(*Interruptions*)...

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: He is making irrelevant points...(Interruptions)...

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं माननीय सदस्य को यह सूचना है कि नहीं . . **(व्यवधान)** . . . मैं उपसभाध्यक्ष महोदय को बोल रहा हूं, आप को नहीं बोल रहा हूं । मेरे पास इस ट्रस्ट के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी है सूचना है कि महाराज जयपुर . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप से जानकारी हम को नहीं लेनी . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उपसभाध्यक्ष को अपनी बात कह रहा हूं । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप इस पर अपनी रूलिंग दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please sit down ...(*Interruptions*)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: You please give your ruling... (*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री जी को इसकी सूचना आएगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Let the Minister reply... (*Interruptions*)...

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं संक्षिप्त में इसकी जानकारी दे सकता हूं। विस्तार से चाहिए तो फिर उस के लिए अलग सूचना चाहिए। संक्षिप्त में यह जानकारी मैंने दी कि यह ट्रस्ट 1921 से कायम है। मैंने ऑनरबल मेंबर को जानकारी दी कि इस ट्रस्ट में एक ही व्यक्ति महाराज जयपुर बाहरी आदमी हैं अन्यथा जितने इस ट्रस्ट के मेंबर हैं वे सब सरकारी हैं। 22 राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त व्यक्ति इसके मेंबर हैं और सरकारी अफसर इसके मेंबर हैं। बाहरी आदमी तो सिर्फ जयपुर के महाराज के द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति और चार केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति हैं। जयपुर महाराज पहले डोनर थे जिन्होंने 15 लाख रुपया दिया था। अब आप जल्दी में नाम नहीं सुनते हैं। विस्तार से चाहिए तो मुझे अलग से सूचना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Just a minute... (*Interruptions*)...I am giving my ruling on this. You see, the honourable Minister himself has admitted that all the information regarding the Trust is not available with him... (*Interruptions*)... Therefore, I just inform the Government that it would have been in the fitness of things if the Government comes out with a statement and when a reference is being made to some institution or trust or fund, all the information is available with the Government. That would have been ideal. Unfortunately, this is not the situation. So, in future, the Government will take care of it. Now, let us close the matter... (*Interruptions*)...

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: It is a question of propriety. You have not applied your mind...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Let us close the matter here... (*Interruptions*)... Now, Mr. Suresh Pachouri

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): महोदय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी के क्षेत्रों में जो चक्रावात हुआ है, वह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यजनक मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य है और अधिक चिंताजनक सरकार द्वारा कोई भी कदम न उठाए जाना है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि सायक्लोन की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी के 6 p.m. कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए है? यह अभी स्पष्ट नहीं है, उनके नाम बताने की कृपा करें। साथ ही जो गेलविण्डस की स्पीड थी, वह स्ट्राइकिंग प्वायंट पर कितनी थी और उसकी अब क्या स्पीड है? उस स्पीड को मद्देनजर रखते हुए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? जो टाइडल-वेव्ज थीं चार से छह मीटर नार्मल लेवल से ऊपर, जिन्होंने साइक्लोन को फोलो किया, वे टाइडल वेव्ज अब कितनी है? यह नार्मल लेवल से कितनी ऊपर है, जिनकी वजह से प्रोप्रर्टी डेमेज हो रही है? चूंकि प्रोपर्टी डेमेज हो रही है, इसलिए सरकार की तरफ से इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास किए गए हैं, वे भी इसमें विस्तार से नहीं दर्शाए गए हैं। क्योंकि जनधन की हानि हुई है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पर्याप्त दवाएं वहां उपलब्ध कराने के लिए, पर्याप्त चिकित्सा-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वहां का दौरा किया है? यह तो बताया गया है कि उप-प्रधान मंत्री जी ने संदेश दिया है, लेकिन क्या उप-प्रधान मंत्री जी, जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया है? नंबर एक स्पष्टीकरण यह चाहूंगा।

नंबर दो, यह एक ऐसा साइक्लोन है, जिसने नवंबर, 1977 के साइक्लोन को भी सरपास कर दिया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, कइयों की जाने गई हैं। इतना होने के बावजूद क्या प्रधानमंत्री जी ने

उस क्षेत्र का दौरा किया है ? यह बताने की कृपा करें ।

तीसरा मेरा प्वाइंट यह है कि जो मौसम विभाग है, उसके बारे में यह बताया गया कि उसने यह अग्रिम सूचना दी थी 4–5 मई को । इस संबंध में मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि समुद्री तूफान की गति आरंभ में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर थी और यह आशा थी कि वह तेज होकर गंभीर समुद्री तूफान मे बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका रुख उत्तर की ओर बदल गया । तो मौसम विभाग के जिन अधिकारियों ने यह गलत सूचना दी, जिनकी वजह से हम अग्रिम कोई कदम नहीं उठा पाए, कोई सार्थक पहल नहीं कर पाए तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? साथ-साथ ही क्या मौसम विभाग ने, आगे भी इस प्रकार का बेदर रहेगा, इस प्रकार का अंदेशा व्यक्त किया है ? यदि अंदेशा व्यक्त किया है तो उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

चौथा, मेरा प्रश्न यह है कि जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम विजयवाड़ा में स्थित है, वह काम नहीं कर रहा है । जब वह काम नहीं कर रहा है तो इससे प्रभावित और किस ढंग से, अलग-अलग क्षेत्र होंगे, इस बात की सूचना हमें नहीं मिल पा रही है और न ही मिल सकेगी। तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे है ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि जिन राज्य सरकारों ने मांग की है, जहां नेवी और आर्मी की जरूरत है, वहां भेज दी जाएगी, मुझे ज्ञात हुआ है कि आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस संबंध में मांग की है तो क्या वहां आर्मी और नेवी भेजी गई है ? इस पर मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

महोदय, जो ट्रस्ट की बात है, उस संबंध में बहुत कुछ स्पष्टीकरण आपको देना है, लेकिन जब इस दृष्टि से मदद दी जा सकती है, वित्तीय मदद दी जा सकती है तो प्रधानमंत्री कोष से इस संबंध में कोई भी मदद न दी जाना अत्यन्त निंदनीय है । टाइडल-वेव की वजह से एक लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या मदद सरकार उनको देने जा रही है ? यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा । धन्यवाद ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, वे आफ बंगाल से उठे इस साइक्लोन में सबसे पहले जो शिपिंग कारपोरेशन का एक जहाज फंस गया था, उसका पता अभी तक नहीं लगा और उसके साथ-साथ उसमें 60 क्रू मैम्बर्स थे, तो उनकी लाइफ या जान-माल की हानि क्या हुई है, यह सदन को अभी तक सूचित नहीं किया गया है । इसके साथ-साथ ऐसे कितने और मछुआरों के जहाज इसमें फंसे हैं और उससे अफेक्टेड हुए हैं ? उनको बार-बार जो वार्निंग दी जा रही थीं, उसके बारे में भी स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा है । इसके साथ-साथ आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु तो बड़े राज्य हैं, ये तो कुछ इस साइक्लोन के धक्के को संभाल भी सकते हैं और केन्द्र से मदद भी पहुंचेगी, पर पाण्डिचेरी, जो एक छोटा-सा राज्य है, उसके बारे में कोई स्पेशल टीम यहां से गई है ? वहां जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में सरकार ने कितना राहत कोष में से पैसा दिया है ? वहां दूध की सप्लाई बच्चों के लिये या मेडिसिन्स वगैरह, जो कि वहां पर पैसा होने पर भी उपलब्ध नहीं है, वह क्या दिल्ली, कलकत्ता या बम्बई से रवाना की गयी हैं या नही की गयी हैं ? डाक्टरों की बहुत कमी है, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और पाण्डिचेरी में । अक्सर पहले ही वहां बीमारियां फैल जाती और खास करके जब साइक्लोन आता है, तब कई और तरह की बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि चेंज होता है, अनहाइजेनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो डाक्टरों की टीम भेजी गयी है या नहीं ?

सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि अभी तक प्रधान मंत्री या उप-प्रधान मंत्री ने इन तीनों प्रान्तों का दौरा नहीं किया है । कम से कम दौरा करके तो दिखायें । दुर्भाग्य एक और भी है कि

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

कल राजा-दर्शन में , जो दूरदर्शन का दूसरा नाम रखा गया है, उसमें जो आन्ध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ एन० टी० रामाराव जा रहे थे, बार-बार एन० टी रामाराव को दिखाया जा रहा था, क्योंकि उपेन्द्र जी उसके मंत्री हैं। शर्म की बात है। वहां भी राजनीति खेली जा रही थी और चेन्ना रेड्डी को दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। यह शर्म की बात है कि जब लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं और उनको रीलीफ में चीजें बांटी जा रही हैं, वहां भी आप रामाराव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।... (**व्यवधान**)...

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: With the Chief Minister he is going there.

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is the Opposition leader... (*Interruptions*).

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: You are not respecting us.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: We are... (*Interruptions*).

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: वही, उसी तरह, जिस तरह हजारों लोग कल राजीव गांधी के साथ अनशन पर गये और आपने दिल्ली पुलिस के नौजवान दिखाये टी०वी० में। शर्म आनी चाहिये। सच्चाई से दूर भाग रहे हैं आप लोग। यह भी क्या उसी की चाल है कि जो वहां ट्रस्ट और वालेण्टरी सर्विसिज हैं, वहां पर वालेण्टरी आर्गेनाइजेशन वहां पर साइक्लोन से ग्रसित लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके नाम न मेंशन करते हुए एक इण्डियन पीपल्स नेच्युरल क्लामिटी ट्रस्ट के नाम का प्रचार करने के लिये और बार-बार सुनाया जा रहा है, सामन्तवाद आ गया है, कि राजा जयपुर, राजा-महाराजा जयपुर का पैसा। इस सरकार को इतनी कमी हो गयी कि अब निर्भर हो गये, राजा और महाराजाओं के ? उनके कोष से पैसा निकालकर हमें बांटना पड़ रहा है। उसका प्रचार कर रहे हैं। वहां पर जो छोटे-छोटे गुरूद्वारों का लंगर चल रहा है, भारत सेवक समाज का लंगर चल रहा है, रेड क्रास सोसायटी काम कर रही है, मदर टैरेसा की आर्गेनाइजेशन काम कर रही है या श्री अरविन्दो का आश्रम काम कर रहा है, उनका उल्लेख नहीं किया गया है, यह शर्म की बात है। इस तरह की घटना, जैसा कि वाइस चेयरमैन साहब ने कहा है, भविष्य में नहीं होगी, मैं इसी बात को सोचते हुए, इस बात को विदड्रा करता हूं। ऐसी घटना भविष्य में वाकई नहीं होनी चाहिये।

महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासकर के कि पाण्डिचेरी का कितना नुकसान हुआ और पाण्डिचेरी को कितना पैसा आपने अलाट किया है ?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I have gone through the Minister's statement of yesterday. I want to ask him a specific question. It is said over here and it was said in yesterday's statement also that the developments were being closely monitored at the Centre by the Crisis Management Group functioning in the Ministry of Agriculture and Cooperation and that various Ministries and Departments have been keeping touch with the State Government authorities and so on. It is very unfortunate that in the whole of yesterday's statement and today's statement they don't make even a single reference to the tremendously commendable work that has been done by the State Government of Andhra Pradesh... (*Interruptions*)... Is it something funny, Dr. Reddy? May be you would like to share the joke with us. I heard funny sounds and I just wanted to find out what it was. I am extremely concerned about it for one reason. The tremendous work that the State Government has done in evacuating more than 1.2 lakh families is laudable. I am concerned with it. That is why I am asking about it. There have been warnings over the radio. The Meteorological Department has done

wonderful work. They predicted and forecast the cyclone. The Disaster Management Group, the Crisis Management Group and everybody else was working. Not a word is said in the statement about what the State Government has done. They have done a tremendous work in evacuating 1.2 lakh families. Relief camps had been kept going continuously for days before the cyclone hit. Not a word is said about that. Never mind.

I am also surprised that not a word is said about the fact that despite all these Crisis Management Groups which have been working. 7000 people belonging to a village called Village Yaduramundi in Andhra Pradesh refused to leave that place. They were told to evacuate. They were told that they were on the direct path of cyclone. They refused to evacuate from there. What was the Crisis Management Group at the Centre doing and what was the State Government doing? I want to know what the Government and the Crisis Management Groups were doing when they allowed these 7000 people of this village to stay in a place where they were going to meet with certain death. I understand that the death toll would have never gone up to 72 or 85 as the newspapers say if it was not for these people who refused to evacuate. When you had evacuated 1.2 lakh families, you could surely evacuate these people who were in the path of the cyclone. Merely on the reasoning of these people that they did not suffer in 1977, should they have been allowed to stay there? Should the choice have been left to these people? I also want to ask him a specific question about the fate of these 7000 people because they seem to constitute the bulk of the stranded population. Today we do not know what the fate of these people is. In yesterday's statement, the Minister has said that Rs. 86 crores and Rs. 39 crores have been given. I want to know how much of the money has already been released by the Centre. Seventy-five per cent of this amount is supposed to be given by the Central Government. How much of it has already been released so that it reaches the State Government.

Apart from that, the first clarification that I want to seek from the hon. Minister is this. Yesterday, one of the hon. Members was pleased to clarify that it was in response to a question from the hon. Member about who the other people are and which are the other kinds of assistance which are being given to the people. In today's statement, he specifically says that this is the further assistance given to the people. Do we take it to mean that the Indian People's Trust is the only other Group which is going forward to help the people? Or are there other groups which are helping the people over there? If there are other Groups, why is it that he has singled out only this Trust for special mention? He must have got that information since that has come forward with a statement today. If there are other Groups, the Red Cross or any other groups, which are helping the people in Andhra Pradesh and in Tamil Nadu, what are these groups? I want to know who they are, what is the kind of work they are carrying out, what is their constitution and what kind of assistance they are rendering to the people. Thank you.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : वाईस चेयरमैन सर, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि सदस्यों ने जो यह इच्छा व्यक्त की है कि यह जो ट्रस्ट है, उसमें पच्चीस हजार रुपये एक व्यक्ति के मरने के लिये दिया है, तो ट्रस्ट के बारे में तो वे विस्तार से बतायेंगे ही, लेकिन जो स्वयं सेवी संस्थायें या और कोई ऐसे ट्रस्ट या और कोई ऐसे आर्गेनाइजेशन्श जो प्रदेश के अन्दर हैं या बाहर हैं, वह अगर सरकार की नालिज में हैं ? मैं यह भी चाहूंगा कि अच्छा होता अगर

[श्री कृष्णलाल शर्मा]

यह जो कुछ किया गया, उसको मैम्बर्स एप्रीसिएट करते और फिर बाकी संस्थाओं का भी मेंशन मांगते तो मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं कि उसके बारे में मंत्री महोदय अगर कुछ जानकारी है, तो जरूर हाऊस को दें।

दूसरी बात, यह जो इतना बड़ा साइक्लोन आया है, उसके परिणामस्वरूप यह संभावना हो सकती है कि वहां महामारी फैले, एपेडेमिक कोई फैल सकता है और कैम्पस् जो लगे हैं, उनकी स्वच्छता के बारे में या उनके अन्दर कोई इस तरह की बीमारी न फैलें, उसके बारे में केन्द्र से क्या सहायता दी जा रही है? प्रदेश से क्या सहायता हो रही है? महामारी को रोकना एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा चिन्ता का विषय बन जायेगा। अभी तक यह बताया जा रहा है कि इस साइक्लोन में शायद 70 और 100 के बीच रेंज में लोग मरे हैं। लेकिन अगर महामारी फैलती है, तो उसका नुकसान बहुत हो सकता है। इसलिये यह मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मंत्रालय की ओर से इसके बारे में पूरी चिन्ता की जा रही है? या नहीं की जा रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने केवल अपने विभाग की दृष्टि से ही कुछ बातें कहीं हैं, तो केन्द्र की तरफ से चाहे वह प्रधान मंत्री कोष है या जो विभिन्न मंत्रालय हैं, उनकी ओर से क्या-क्या सहायता इस समय वहां दी गयी है? और उस सहायता का वहां पर ठीक तरह से वितरण हो और लोगों तक पहुंचे, उसको मॉनिटरिंग करने के लिये यहां केन्द्र में क्या व्यवस्था की गयी है? इसकी जानकारी मंत्री महोदय दें, इतना मैं जानना चाहता हूं।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a very serious cyclone that has hit the Andhra Pradesh coast. I know about the cyclones, especially the 1977 cyclone when I was in the Andhra Pradesh Government service, and I was totally in charge of the medical relief operations at that time. In that cyclone, Sir, no less than 20,000 people had died and 2 lakh cattle perished and the entire area was filled with darkness for about 6 to 7 days. People were marooned... (*Interruptions*) I am trying to say that the enormity of the problem is always there. Now, about 15 lakhs of people are shelterless, and these are the persons who belong to the poorer classess who reside in low lying areas. Their houses are washed away. They are not able to get even potable water. That is the situation that is reported in the press. In Vijayawada city, the water supply system has collapsed and they are not able to supply even half of what they used to regularly supply. If the supply of potable water suffers, then the danger of spread of infections will be there. That is why I want to ask the hon. Minister as to what extra efforts he is going to take so that potable water is supplied to all these 15 lakh people who are marooned, who are helpless at this particular stage. It has also come to our notice that essential commodities are not adequately supplied. The prices are going up. Vegetable prices are going up. It has become very difficult for those persons to carry on. So, I want to know what special assistance the Government of India so also the State Government are going to give, and how they are going to be provided with the supply of essential commodities, utensils and shelters. As Mrs. Jayanthi Natarajan has stated, the State Government has taken very correct steps. 1.5 lakhs of people have been evacuated. But for that, the calamity, the death toll could have been much more. In that particular context, I do not grudge giving very good appreciation to the efforts that have been made by the State Government, and they are in a position to contain the calamity. And in this context, I also want to mention that a lot of area, about 100 villages are completely washed out, especially those on the shores. Their lands

have been filled with saline water and they will not be fit for cultivation for quite a long time. A number of fruit gradens, including mango, and betelnut plantations have been washed away. The problems faced by the farmers are enormous. How does the Central Government propose to help the farmers? This is also one of the major questions which has to be dealt with by the hon. Minister.

Then, Sir, some of the large poultry farms have been washed away. Mr. Vice-Chairman, Andhra Pradesh is one of the leading producers of eggs and other poultry products. A lot of damage has been caused to these poultry farms.

It is still raining there. Till tomorrow it will be there. Therefore, it will be sometime before we know the full magnitude of the problem. My question is, will the Government of India send a team of officers to work in co-ordination with the State Government officials and build up a rapport with them? This team can find out what all is required by the State Government and rush help immediately. I would like to know whether arrangements have been made in this regard. We made this request, about sending a Central team, yesterday also.

Because of gale and wind, helicopters have been unable even to drop food. This means, quite a section of the marooned population is starving. What special steps are being taken to see that food and other things are supplied to the marooned population? In regard to voluntary agencies, the Chief Minister has already made an appeal to all the voluntary agencies to come forward with help. I am happy to note that responding to what the hon. Members said yesterday, the Central Government has decided to grant Rs. 25,000 in the case of each death from some fund. It is good to note that Rs. 25,000 more is being given to the bereaved families.

Even now, the death toll is 95 and it may be much more by tomorrow or the day after. Now, rail, road and other communications are cut. The actual figure will be known only when the communications are restored. We do not have the correct information now from all the villages. About a thousand villages have been affected. About a hundred villages have been completely submerged. This is a grave tragedy. That is why I say that we should have full information for proper assessment. As I said, a Central team should be sent immediately to establish a rapport with the State Government officials. The Prime Minister should visit the affected areas. We should go to the rescue of the people of Andhra Pradesh in a big way and we should stand by them in their hour of tragedy. I hope, some good gesture will be shown by the hon. Minister.

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very sorry to say that the statement made by the hon. Minister is too cryptic, too brief and also outdated because you must have seen in the newspapers that the death toll has gone up to 96 although the Minister puts the figure at 72. Official sources in Madras have said that seven deaths have taken place in Tamil Nadu. In the statement he has said that it is only one.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: He has given the correct figure.

SHRI KAPIL VERMA: Has he corrected it? All right. The point is, there is not that much seriousness. Of course, there is the crisis management group in operation. But I am afraid, the seriousness, the gravity of the situation demands of the Central Government is not reflected in the statement. I hope I am wrong. But awareness of the gravity of the situation is not there in the Centre's handling. I am not doubting their intentions or their motives. But unfortunately, we have not woken up.

[Shri Kapil Verma]

to the situation very rapidly. In this connection, I must congratulate the Andhra Pradesh Government for the wonderful work they have done. They have done tremendous work. The Chief Minister had said that six lakh people were shifted, but the Central Government says that only one-and-a half lakh were shifted.

There are one or two points on which I would like to seek clarification. What is the number of villages which have been marooned? There is a mention of 'hundred' somewhere. Different figures are given. Then, nine helicopters laden with food could not take off a few days ago. Have these hlicopters been able to take off now to drop food to the marooned people? What is the number of the marooned people? Even the elementary information that is generally given in the case of floods is missing from this statement. The statement has not given the information like the total population affected. the total number of villages affected, the total damage to crops because in coastal and other areas there is a colossal damage to the crops. I want to know how much damage has been done.

What is the number of the houses that have collapsed because as the water recedes there are house collapses? What is the position of electric supply? The newspaper report says that Vijaywada power station is damaged or something like that. Power supply has been affected and it has affected water supply also. Communication has broken down. So, we want a comprehensive statement giving all these details. I hope this is not the intention of the Government, but the Government must take precautions to ensure that no impression is created that we are belittling the State Government's performance. You are publicising trusts and other sources of donations, but the State Government is also doing equally good work. I hope the Government will come forward with a more detailed statement, how you are feeding the people, how you are managing relief works. In 1977 cyclone 10,000 people had lost their lives. This time there is a loss of 72 or 86 lives and this is only because the State Government has quietly geared itself into action. I hope the Government will come forward with more detailed statement.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to make some pointed queries because lot of things have already been inferred. My first point is that the Chief Minister has said that the earlier practice of a Central team visiting the calamity-hit areas to assess the damage has been dispensed with. If that is so, no Central team has been sent for assessment of damages or what kind of help is required. So no assessment has been done. If so, would any Central team be sent or is there any plan to send a Central team in this respect?

Then, Sir, super computers can give nearly correct prediction for 15 days in advance. Was this information about cyclone predicted or not? If not, who is responsible for this? If yes, what steps did the Government take to evacuate the people to avoid this kind of calamity?

How many are stranded even now and what efforts are being made to evacuate them?

Is there any further prediction for cyclone during the next 15 days?

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala): It has been stated that a crisis management group is there. Even though the financial help has been given to the State Government in time and the Prime Minister is visiting the place tomorrow, I am seeing some lacuna in the statement.

Has any special Central team been sent to Andhra, Tamil Nadu and Pondicherry? If not why? When it was found that the helicopters could

not take off, was any help sought from the Air Force? Were they asked to render the necessary help?

Another thing is, more than 5 lakh people have been shifted. As my friends have said, crops have been destroyed, land has been destroyed and so much damage has been there. What steps are going to be taken by the Government to see that compensation is paid to them? For the persons who have died, compensation has been decided upon. That is good. But at the same time, compensation should be paid to the agricultural workers because their land cannot be cultivated for a long time. It is covered with saline water. So what steps have been taken by this Government for giving them protection? Their houses have been destroyed, their cattle have been destroyed. So what measures are going to be taken by the Government to give them protection? Fodder has also been lost. That has also to be provided. Even though the Meteorological Department had been able to predict it earlier and thereby the damage has been lessened down, yet this is a very serious thing which has to be taken note of. Immediate steps have to be taken in that regard. Thereafter it is going to prolong for a certain period because cultivation cannot be done, they cannot go to their houses and they are being forced to live in relief camps. Food has to be dropped. Now for two days the helicopters could not take off. So how can the food be dropped? The Air Force has not been taked to drop food. Even though a crisis management group is there, crisis management means that they must see that immediate steps are taken. Is the Government prepared to do that? That is what I want to know.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Shri Ram Naresh Yadav.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): य, जिस तरह से चक्रवात के कारण तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में पौर धन की क्षति हुई है और जैसे लोग मरे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सारे देश की सहानुभूति इसमें जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ है। किन्तु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना घटी है, हुई है, वैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण माननीय मंत्री जी का यह बयान भी है, जो आज सदन में दिया गया है। मैं इसे जो दुर्भाग्य कह रहा हूं वह इसलिये कह रहा हूं कि कल भी एक बयान आपने दिया और आज भी एक बयान दिया। लेकिन इस बयान में, महोदय, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह बात कभी कभी बहुत तकलीफदेह होती है जब सदन के अन्दर इस तरह का बयान आता है और जब सरकार सही मामलों को सही ढंग से नहीं रख पाती है तो देश के लिये यह चिंताजनक स्थिति होती है। आपने अपने बयान में यह कहा कि "हाल ही में आ. चक्रवात के कारण मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में" मायने जो लोग मरे हैं, उन मरे हुये लोगों को वित्तीय सहायता देने के बारे में सदन की अनुमति आपने चाही है। उसके बाद फिर कहा गया है कि "माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने कल इस आपदा के कारण हुई कुछ मौतों के बारे में सदन में एक वक्तव्य दिया था।" मैंने इसलिये कहा कि यह बयान दुर्भाग्य पूर्ण है अगर यह बयान में आता और माननीय मंत्री जी भविष्य में जब कभी इस तरह का बयान उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से आये तो उसको बहुत गंभीरता से पढ़ने और विचार करने के बाद ही उसको अपनी स्वीकृति दे। इसलिये मैं संकेत कर रहा हूं कि अच्छा होता अगर व कहते कि कल मैंने चक्रवात से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया। अगर ऐसा होता तो बात समझ में आती और उसमें सारी चीजों का उल्लेख होता। लेकिन बयान में केवल मौतों और वित्तीय सहायता के बारे में उल्लेख है इसलिये यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा और जैसे मेरे अन्य साथियों ने इशारा किया कि राज्यों में मुख्यमंत्री कोष होता है और जब कभी ऐसी घटनायें होती हैं तो मुख्य

[श्री राम नरेश यादव]

मंत्री अपने कोष से ऐसे मामले में व्यवस्था करता है ताकि कहीं पर अगर इस तरह की स्थिति आये जिससे जन और धन की हानि व्यापक पैमाने पर होती हो तो उसका मुकाबला किया जा सके । इसी तरह से केन्द्र में भी प्रधान मंत्री राहत कोष होता है । मैंने इसलिये दुर्भाग्यपूर्ण कहा कि अगर इस वक्तव्य में यह आया होता और सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ इस घटना को लिया होता अगर इस बात की व्यवस्था हो गई होती कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कोष से इतना लाख रुपये, इतने करोड़ रुपये की तात्कालिक सहायता देना स्वीकार किया है तो भी एक बात समझ में आती कि सचमुच में प्रधानमंत्री जी के कोष का उपयोग हो रहा है । मैं जानना चाहूंगा ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री जी के कोष से या सरकार की तरफ से क्यों नहीं बात आती । दूसरी बात यह है कि एक तो जो स्थिति है उसमें कई तरह के सवालात पदा हो रहे हैं । इतनी बड़ी स्थिति पैदा हो गई, लोगों का नुक्सान हो गया, विशेष रूप से मछुआरे और किनारे पर रहने वाले लोगों का, यह भी इस बयान में नहीं आया है कि आपने कोई यहां से राज्य सरकार मांगें या न मांगे लेकिन मानवता का प्रश्न है, जहां पर इतने सारे लोगों को जिन्दगी का सवाल जुड़ा हुआ है, विस्थापित हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिये केन्द्र ने अपने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर के कोई ऐसी टीम विशेषज्ञों की सारी चीजों से सजग होकर भेजने का काम क्यों नहीं किया है ? और अगर ऐसा नहीं किया है तो आप कब तक इस काम को कर लेंगे ? तीसरी बात यह है कि आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव ऐसे समय में हो जाता है । जैसे मेरे एक साथी कह रहे थे बात सही है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ इस मामले को उठाने का काम किया हैं लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है आंध्र प्रदेश सरकार इसके लिये धन्यवाद और बधाई की पात्र है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति है तो जो आवश्यक वस्तुयें हैं सरकार मांगें या न मांगे आप चीनी का कोटा समय समय पर रिलीज करते हैं और कई महीनों के बाद रिलीज करते हैं और चीजें समय पर नहीं पहुंच पाती है । ऐसी स्थिति में बिना सरकार द्वारा मांगे सरकार के यहां से पत्र आये बिना आपने उस दिशा में कदम न उठाकर असावधानी बरतने का काम किया है । आवश्यक वस्तुयें इस तरह से भेजें ताकि वहां पर संकट की घड़ी में सामान उपलब्ध हो सके । आप यहां से मासिक-वार जो आवश्यक वस्तुयें राज्यों को भेजते हैं उसको जल्दी से रिलीज करने का काम करेंगे और देखेंगे कि वह सही ढंग से पहुंच जाय। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों आसाम में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी और कलकत्ता में चक्रवात आया था । यह मैं इसलिये कह रहा हूं यह जिस ट्रस्ट की बात आई है इस सदन के अन्दर, वैसे तो आपकी व्यवस्था हो गई है मंत्री जी उस पर बयान देंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सदन में इस ट्रस्ट की व्यवस्था को लाकर अकारण ही एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया गया है जो इस सदन से संबंधित नहीं है सरकार से संबंधित नहीं है यह तो बाहर का ट्रस्ट है जितना चाहे सरकार रुपया दे दे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई अपील नहीं की, इस वक्तव्य में भी कहीं नहीं है, कल वाले वक्तव्य में भी नहीं है । प्रधानमंत्री जी ने कोई अपील नहीं की । देश में इतनी बड़ी घटना हो जाय, सारे लोगों की जानमाल का खतरा हो जाय, घर नष्ट हो जायें, रहने का साधन न रहे, खाने-पीने का साधन न रहे लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी भी इस तरह की अपील देश की जनता के सामने न आना इस बात को शो करता है कि प्रधान मंत्री कितने संवेदनशील हैं । इसलिये ऐसी स्थिति में मैं एक प्रश्न यह भी करना चाहता हूं कि जबकि आपने अधिकारियों को लगा दिया, राज्य सरकारों को भी लगाया है, क्या इस सदन की तरफ से कोई टीम भेज कर वहां की वस्तुस्थिति को और भी गहराई से

not take off, was any help sought from the Air Force? Were they asked to render the necessary help?

Another thing is, more than 5 lakh people have been shifted. As my friends have said, crops have been destroyed, land has been destroyed and so much damage has been there. What steps are going to be taken by the Government to see that compensation is paid to them? For the persons who have died, compensation has been decided upon. That is good. But at the same time, compensation should be paid to the agricultural workers because their land cannot be cultivated for a long time. It is covered with saline water. So what steps have been taken by this Government for giving them protection? Their houses have been destroyed, their cattle have been destroyed. So what measures are going to be taken by the Government to give them protection? Fodder has also been lost. That has also to be provided. Even though the Meteorological Department had been able to predict it earlier and thereby the damage has been lessened down, yet this is a very serious thing which has to be taken note of. Immediate steps have to be taken in that regard. Thereafter it is going to prolong for a certain period because cultivation cannot be done, they cannot go to their houses and they are being forced to live in relief camps. Food has to be dropped. Now for two days the helicopters could not take off. So how can the food be dropped? The Air Force has not been taked to drop food. Even though a crisis management group is there, crisis management means that they must see that immediate steps are taken. Is the Government prepared to do that? That is what I want to know.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Shri Ram Naresh Yadav.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, जिस तरह से चक्रवात के कारण आंध्र, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में जन और धन की क्षति हुई है और जैसे लोग मरे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सारे देश की सहानुभूति इसमें जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ है। किन्तु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना घटी है, हुई है, वैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण माननीय मंत्री जी का यह बयान भी है, जो आज सदन में दिया गया है। मैं इसे जो दुर्भाग्य कह रहा हूं वह इसलिये कह रहा हूं कि कल भी एक बयान आपने दिया और आज भी एक बयान दिया। लेकिन इस बयान में, महोदय, यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह बात कभी कभी बहुत तकलीफदेह होती है जब सदन के अन्दर इस तरह का बयान आता है और जब सरकार सही मामलों को सही ढंग से नहीं रख पाती है तो देश के लिये यह चिंताजनक स्थिति होती है। आपने अपने बयान में यह कहा कि "हाल ही में आए चक्रवात के कारण मरने वालों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में" मायने जो लोग मरे हैं, उन मरे हुये लोगों को वित्तीय सहायता देने के बारे में सदन की अनुमति आपने चाही है। उसके बाद फिर कहा गया है कि "माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने कल इस आपदा के कारण हुई कुछ मौतों के बारे में सदन में एक वक्तव्य दिया था।" मैंने इसलिये कहा कि यह बयान दुर्भाग्य पूर्ण है अगर यह बयान में आता और माननीय मंत्री जी भविष्य में जब कभी इस तरह का बयान उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से आये तो उसको बहुत गंभीरता से पढ़ने और विचार करने के बाद ही उसको अपनी स्वीकृति दे। इसलिये मैं संकेत कर रहा हूं कि अच्छा होता अगर व कहते कि कल मैंने चक्रवात से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया। अगर ऐसा होता तो बात समझ में आती और उसमें सारी चीजों का उल्लेख होता। लेकिन बयान में केवल मौतों और वित्तीय सहायता के बारे में उल्लेख है इसलिये यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा और जैसे मेरे अन्य साथियों ने इशारा किया कि राज्यों में मुख्यमंत्री कोष होता है और जब कभी ऐसी घटनायें होती हैं तो मुख्य

जानने का काम करेंगे और उनके काम में जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको भी सुधारने की दिशा में आप प्रयास करेंगे । आपने कहा है कि नजर रख रहे हैं, कल भी कहा था, कल से आज तक इस बयान के देने के समय तक, जितने राज्यों में लोग पीड़ित हैं उनके बारे में लेटेस्ट आप यह बतायें कि राज्यों से किन-किन चीजों की डिमांड आपके पास आई है और उस डिमांड को पूरा करने के लिये क्या क्या कदम आपने उठाये हैं, यह भी हम जानना चाहते हैं ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु में घटी है । बड़े दुख की बात है कि माननीय मंत्री जी ने कल भी निवेदन किया । आज भी निवेदन किया, मैं उनको खूब धन्यवाद देता हूं । इसमें कहा गया है कि 72 व्यक्ति मरे हैं । बहुत सी बातें बतायी गयी हैं लेकिन मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग मरे हैं वहां पर उन परिवारों में जो प्रमुख लोग मर गये हैं उनके बच्चों और महिलाओं के लिये आप जो धनराशि देने जा रहे हैं उसमें बढ़ावा करके क्या आप राज्य सरकारों को यह डिटेल सूचना देंगे कि ऐसे परिवार जिनमें मुख्य आदमियों की मृत्यु हो गयी है इस घटना में ऐसे परिवारों को आइडेंटीफाई करके कुछ ज्यादा सहूलियतें या कुछ ज्यादा देना चाहिये । ऐसा केन्द्र सरकार करने जा रही है या नहीं ? दूसरा, एक बात खबर में ऐसी भी निकली है कि इस चक्रवात का कुछ असर गुजरात के बड़ौदा जिले के छोटा उदयपुर में भी हुआ है । क्या यह जानकारी आपके पास है । यह आपने जो स्टेटमेंट किया है उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है । यह जानकारी आप हमें दें । तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा जैसे अभी राम नरेश यादव जी ने कहा कि दोनों सदनों के सभी दलों के लोगों की एक टीम बनाकर तीनों प्रदेशों में भेजेंगे जो देखें कि केन्द्र और राज्य सरकारों की जो आर्थिक मदद जिन लोगों को मिलनी है वह उन्हें अच्छी तरह से मिले । क्या ऐसी कोई योजना बनाकर आप सदन के सामने रखना चाहते हैं ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Unfortunately the statement is too cryptic and only three things have been highlighted—the number of deaths, the amount of money, Rs. 25,000, and the trust which has been identified.

The cyclone has brought a lot of problems for the people who have been directly hit. There is no doubt about it. There is a crisis management group. I only hope this crisis management group is not busy overtime managing political crisis and has enough time to manage such calamities which lead to different kinds of crises.

More specifically now that the early warning system has been working for some time, is there any evidence to show that its effectiveness is becoming better Was that better performance available this time leading to more timely precautions and corresponding precautionary steps by the people?

Second, I am somewhat distressed with this amount of Rs. 25,000 appearing uniformly. Any death is unfortunate for that person and for that family, but some death brings greater misery. Take, for example, if there is a death of a breadwinner in the family and a death of a child who is a promising child and who has all the possibilities of becoming an asset in the society, is the amount of compensation going to be uniform in all situations or there is some provision that the incidence of calamity and economic misery inflicted as a result of one or the other death will be assessed differentially and correspondingly the amount of compensation in the first round or the second round or the subsequent round will be different? If not, will the Government consider this possibility as the policy evolves?

the death toll is only 81 and we do not know how much money is left in the Trust. Will this yardstick apply to all those deaths that may occur subsequently? So far the death toll is 81. According to the Minister himself the money was only Rs. 50 lakhs. (*Interruptions*). Anyway, he must be able to tell us if the death toll goes up, will the yardstick of Rs. 25,000 apply to any number of deaths that may occur—God forbid, it should not happen—but if for unfortunate reasons, some more deaths are to occur or are to be found out, might have occurred because of this situation—if some more deaths are identified, will the yardstick of Rs. 25,000 continue for all those deaths that may occur in the area? And lastly, Sir, I want to go on record that the House is not happy about the information that we have got till now. I request the hon. Minister to come out with a detailed statement on Monday again about the latest position of marooned people, latest position of the reliefs that reached the people. I expect that there will be an assurance from the Minister to come out with another statement on Monday about the latest position of the relief measures.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, the statement which has been made by the hon. Minister is not a detailed one and it leaves everything to be desired. The hon. Members have pointed out the lines on which the hon. Minister should give information to the House and rightly so because a big calamity has struck the nation and the whole nation and Parliament would like to know the details of the same and the manner in which the Government is going to deal with this unfortunate situation. The statement is silent on the number of persons injured. The hon. Minister will kindly take care to inform the House about the same and whether the injured will also be given succour and help. The statement is silent as to the number of houses destroyed. The statement is silent as to the cultivated land which had been innundated and may be unfit for cultivation. The statement is silent as to the cattle which have been lost. The statement further does not show as to what amount of damage has been caused to water and electricity needed by the people for drinking, for lighting and other purposes and how that damage is going to be set right and in how much of time. The statement says "I would like once again to assure the House that the Government of India is keeping a close watch on the situation and will render all possible assistance as and when required by the affected State Governments."

I think the State Governments must have requested by now what assistance they require from the Central Government. The statement should also make it clear and the hon. Minister may kindly come to the House posted with all these facts and further state as to how much help the State Governments have asked for so far. The work that the State Governments have done compared to the losses suffered in 1977 *prima facie* appears to be commendable in as much as the loss of life has been contained. But I would say that it would be too optimistic to make an exact assessment at this time because the communication network is not working and the system has collapsed and we are not aware of what has happened and how many have died in 1000 villages which have been totally submerged and in hundreds of villages which are submerged. Therefore, the minimum that a Government responsible to the people can do is to come forward with a statement which satisfies the people, which satisfies Parliament and which gives the necessary information. Moreover, the Government should show its awareness as Mr. Ram Naresh Yadav has pointed out, by the Prime Minister appealing to the nation and asking the nation to rise to the occasion and come to the rescue of the brethren who have been suffering on account of the cyclone.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Mr. Vice-Chairman..... (*Interruptions*). In fact, I have nothing much to say because the Central Government has nothing much to say either. The Central Government has nothing much to say. Yesterday that

[Shri Vishvjit P. Singh]

had been pointed out by everybody. Even today, the Central Government has nothing much to say. The Central Government has said, the Minister has said, in his statement:

> "Gale force winds of 200—220 kms. per hour and surge of sea to a height of 5 metres above the normal astronomical tidal level were predicted which are likely to inundate low-lying coastal areas of Prakasam, Guntur, Krishna, West Godavari and East Godavari districts of Andhra Pradesh."

In the next pragraph he says:

> "A fuller assessment is yet to be made by the State Government and further details are awaited."

This was the prediction about the tidal wave. This was the prediction about the areas you thought would get inundated. Now the information must have come. The areas must have got inundated. The tidal wave must have come by now as predicted. And what is the situation now? Which are the areas that are affected? Is it confined to these areas which you predicted or is it less or more or, are there other areas? About 1.5 lakh of people, in a very very lightning operation by the State Government, which has to be commended, have been moved out of lawlying areas. It is not just 1.5 lakh. As an hon. Member from the other side just said, over five lakh people have been affected. I would like to know this. In spite of that evacuation, how many people are affected by this tidal wave?

My second point is this. Let me make this very very categorically clear to this House that I welcome any assistance which is made for such a noble cause. I would still like to know two points from the hon. Minister. Firstly, it is incorrect to fix a norm over death. You cannot put a price on it. There is no question of anybody trying to put a price on death. But the fact is that it is unfortunate that we have to fix norms. So the norm fixed by the Government is Rs. 50,000/- per death whether it is through fire or whether it is through communal riots or whatever. It has been so for some time. Now why have you confined it to Rs. 25,000/- only? (*Interruption*). Is it going to be one lakh? I do not know. (*Interruption*).

श्री उमेन्द्र नाथ वर्मा : 77 में मरने वालों को कितना दिया था ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : 77 में आप का राज था, आपने दिया था। ...(व्यवधान)...

श्री हरदेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : भागलपुर में एक लाख रुपया दिया गया, गुजरात में भी एक लाख दे रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : मंत्री जी, 77 के बाद 12 साल बीत गये हैं। उसके बाद के विषय में सोचना चाहिये।

7.00 P.M.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Sir, I am very grateful to you...(*Interruptions*)... Sir, if the honourable Minister interrupts, I will wait for him. Let him say what he wants to say and then I will proceed... (*Interruptions*)...

Sir, I have one very very major problem. It is a moral problem, it is an ethical problem. It is very unfortunate. I do not think it is a problem of procedure. I do not know how to define it correctly. If today a notorious smuggler like Dawood Ibrahim is wanted by the Indian Police and he has escaped from the country and he sets up a relief fund or trust for victims of calamities, would the honourable Minister accept that money? I would like to know that. I am not trying to equate the feudal lord, the Maharaja of Jaipur, with Dawood Ibrahim; I am not doing that. But I feel that the point that the Minister has made is—he has made it very clear—that it is not a public administered trust, but it is a private trust. He has made it very clear. Even if the Agriculture Minister is the *ex-officio* Chairman of that Trust, it is a private Trust. It is not managed by the Agriculture Minister; it is managed by private individuals.

It is quite clear. If it is managed by public servants, the Minister would have made it clear. But there is hesitation on the part of the Minister and it is the hesitation on the part of the Minister which makes me also hesitate in my judgment on this Trust. I have a little problem here and I would like the honourable Minister to clarify these two points. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, Mr. Hanspal. Kindly be brief.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक-दो बातें कहनी हैं। एक तो जैसा अभी विश्वजित पृथ्वीजित सिंह जी ने भी कहा कि यह 25,000/- रुपये का अनुदान तो इंडियन पीपल्स नेचुरल कैलेमिटीज ट्रस्ट दे रहा है तो सरकार और क्या दे रही है? इस बारे में बड़ा स्पेसिफिक जानना चाहता हूं। यह तो ट्रस्ट का रुपया है और सिर्फ 25,000/- दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत जल्दी आपने फैसला किया। मैं उम्मीद करता हूं और जानना चाहता हूं कि यह बहुत जल्दी नेक्स्ट टू दी किन्स को दे दिया जायेगा और सरकार क्या दे रही है?

नम्बर दो, जिनका नुकसान घरों का हुआ है, फसलों का हुआ है, और दूसरे बहुत सारे नुकसान वहां पर हुये हैं उनके लिये सरकार क्या कर रही है?

तीसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि इंडियन पीपल्स नेचुरल कैलेमिटीज ट्रस्ट ने पहले भी कभी इस तरह से रुपया दिया था और अगर दिया था तो कब और कितना दिया था और क्या पार्लियामेंट को इस बारे में सूचित किया गया है? इन पर मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चहूंगा।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से माननीय सदस्यों के सुझावों को सुन रहा था। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि मैंने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है, वह अभी एक बजे तक की जानकारी के आधार पर दिया है। जो क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप कृषि मंत्रालय में स्थिति है, उस ग्रुप की बैठक एक बजे हुई और उस बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी के प्रतिनिधियों से सूचना मांगी गई और उसी सूचना के आधार पर, यह जो लोग इसमें मारे गये हैं, मैंने अपने बयान में उल्लिखित किये हैं। उस बैठक में उन तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों से पूछा गया स्थिति के बारे में और खासकर के दवाइयों के बारे में उन्होंने बताया कि दवाइयां उनके पास अभी प्रचुर मात्रा में हैं और जैसे ही दवाइयों की कमी होगी, हमें तुरन्त सूचित करेंगे। यह भी सूचना मिली कि वहां पर अन्य सामान है। मैंने पूछा, वहां बैठक में यह पुछवाया गया कि इसका ब्यौरा दे सकते हैं? उनके ब्यौरों को तैयार करने में समय लगेगा। अभी तो राज्य सरकार राहत कार्य पहुंचाने में व्यस्त है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 6 हेलीकाप्टर्स की मांग की थी और 6 हेलीकाप्टर्स की मांग की जगह 12 हेलीकाप्टर्स हैदराबाद में विशाखापत्तनम में पहुंच चुके हैं और 3 हेलीकाप्टर और भी पहुंचने वाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता हूं। लेकिन 12 हेलीकाप्टर एयर फोर्स के रेडी हैं हैदराबाद में और विशाखापत्तनम में। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो मैंने बयान दिया यहां और लोक सभा में और ब्यान देने के बाद जो माननीय सदस्यों के सुझाव आये, उन सुझावों को लेकर मैं सीधे यहां से डिप्टी प्रधान मंत्री व कृषि मंत्री के यहां चला गया। वे बीमार हैं, अस्पताल में हैं और मैंने उनसे कहा कि स्थिति भयावह है साइक्लोन की वजह से और जो मेम्बरान हैं, उनकी यह ख्वाइश है और उन्होंने जो सुझाव दिया है, ऐसा लगता है कि उसको तुरन्त मानना चाहिये, विचार करना चाहिये तो माननीय कृषि मत्री जी ने तुरन्त कहा कि पहले तो कुछ पैसों का इंतजाम करो। जो मर गये हैं, उनके परिवार वालों के लिये पैसा दिया जाय और उन्होंने पूछा कि

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

वह जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में कुछ पैसा है या नहीं ? मैंने कहा कि उस ट्रस्ट के चेयरमैन कृषि मंत्री होते हैं और उस ट्रस्ट की कमेटी में 22 राज्यों द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी शामिल है, उस ट्रस्ट में जो भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, वे भी शामिल हैं। उस ट्रस्ट में राज्य में से एक ही आदमी बाहर का आदमी है और वह है राजा जोधपुर। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : अभी तो आपने जयपुर कहा था।

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा: जयपुर कह रहा हूं, जोधपुर गलत है। तो जब इस ट्रस्ट का गठन हुआ था तो पन्द्रह लाख रुपया महाराजा ने उस समय दिया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसीलिए हमारा ध्यान विस्तार के साथ ट्रस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने की ओर नहीं गया बल्कि जल्दी से जल्दी राहत देने की ओर गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1990 तक जो राहत पहुंचाने का तरीका था वह कुछ भिन्न था। पहले यह होता था कि जब किसी राज्य में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए या कहीं कोई अकाल या साइक्लोन या इस प्रकार की घटना घट जाए, तो राज्य सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है, तो राज्य सरकार मांग करती थी भारत सरकार से, केन्द्रीय सरकार से और केन्द्रीय सरकार की ओर से एक टीम जाती थी वहां पर और टीम जो है वह जायजा लेती थी और जायजा लेने के बाद आती थी, तब यहां से फण्ड जाता था, लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : यह गलत ब्यान है। यहां से प्रधान मंत्री, जब भी कुछ होता था, एकदम, तत्काल प्रधान मंत्री वहां उसी जगह, उसी समय अनाऊंस कर देते थे कि इतने करोड़ रुपया हमने दे दिया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड सेन्ट्रल, गवर्नमेंट ग्रान्ट से एकदम तत्काल हो जाता था। ऐसे नहीं जैसे मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि उस तरीके में भी हेर-फेर कर दिया गया है और 1 अप्रैल, 1990 से यह किया गया है कि राहत कोष हर सूबे के लिए अलग-अलग कर दिय गया है और यह कहा गया है कि वह जितना चाहें धन खर्च करें और जरूरत पड़े तो तुरन्त फाइनेंस विभाग को लिखे और जिसके बारे में मैंने कल ही सदन में ब्यान दिया।

एक जहाज के बारे में चर्चा की गई उस जहाज का नाम "विश्व मोहिनी" । जहाज फंस गया था, लेकिन अब वह सुरक्षित है। उसकी मशीन में कहीं कुछ गड़बड़ी आ गई है और उसकी मदद के लिए और जहाज वहां पहुंच गए हैं। इसके बाद की जानकारी अभी हमको नहीं है।

मैंने कल भी कहा था कि जो राज्य सरकार और भारत सरकार ने लोगों को बता दिया था कि साइक्लोन आने वाला है और खतरे से बचिए, यदि इस प्रकार नहीं बताया जाता तो ज्यादा जानें जातीं, ज्यादा लोग मरते।

महोदय, अब प्रधान मंत्री जी के बारे में कहूंगा। प्रधान मंत्री जी ने कार्यक्रम बनाया है और प्रधान मंत्री जी वहां जाने वाले हैं। महोदय, शनिवार को वह जाने वाले हैं और वह वहां की हालत का जायजा लेंगे। मैंने अपने बयान में कल और आज फिर यह कहा है कि जो भी जरूरत होगी वह पूरी की जाएगी, जितनी जहां आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता की पूर्ति होगी।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मंत्री जी आप सोमवार को फिर बयान देंगे ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: इसकी जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपने तो जवाब दिया ही नहीं।

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : अभी जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, वह तो ठीक है। उसमें आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। आप लोग हमें सहयोग दें।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : आप जवाब दें।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : एक सदस्य ने गुजरात के बारे में पूछा था, तो उसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो गुजरात के चक्रवात के बारे में हमारे कार्यालय को जानकारी नहीं मिली है।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : महोदय, मंत्री जी ने यह कहा कि एक बजे तक जितनी जानकारी थी, उस पर उन्होंने जल्दी से जल्दी फैसला कर दिया। इसीलिए इनको यह मालूम नहीं हो सका कि इस ट्रस्ट की क्या डिटेल्स हैं। अब यह ट्रस्ट की डिटेल्स हमें कब बतायेंगे ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : जितनी जानकारी है, वह मैंने बता दी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कितना पैसा है उसमें ? आपने तो कहा कि बिना जाने-बूझे, हड़बड़ी में हम लोगों ने ट्रस्ट को एनाउंस कर दिया। उसमें कितना पैसा है ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने पहले ही कहा कि ट्रस्ट के बारे में पूरे विस्तार के साथ जानकारी अभी नहीं दे सकता हूं लेकिन संक्षेप में जानकारी दे सकता हूं और संक्षेप में मैंने जानकारी दे दी है।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : वाईस चेयरमैन महोदय, जब हमारी बात पूरी हो जाए, तब मंत्री जी बोलें और रनिंग कमेंट्री न करें और जब हम अपनी बात खत्म कर लें तब जवाब दें। इन्होंने यह कहा कि मैं ट्रस्ट के बारे में जानकारी इसलिए नहीं ले सका कि हम लोगों ने जल्दी में यह फैसला किया। तो हम यह जानना चाहेंगे कि उस ट्रस्ट के बारे में वह हमें कब जानकारी देंगे ? ट्रस्ट ने पहले क्या काम किए, ट्रस्ट के पास कितने पैसे हैं . . . (व्यवधान)

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : जानकारी सारे सदस्य चाहते हैं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने पहले ही कहा है कि आपको वह जानकारी मिल जाएगी। यह ट्रस्ट 1900 ईस्वी से काम कर रहा है . . . (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : महोदय, आपने इस बात पर रूलिंग दे दिया है, मिनिस्टर ने भी जवाब दे दिया है। एक ही बात अब रह जाती है कि क्या आप लोकसभा और राज्य सभा के मेंम्बरों की समितियों का गठन करने की घोषणा करेंगे ?

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : प्रधान मंत्री जी बहां जा रहे हैं। मंडे को आप स्टेटमेंट दीजिए।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैंने एक प्रश्न उठाया था कि जब चक्रवात से इतना अधिक नुकसान हो गया है तो सारी जनता को आश्वस्त करने के लिए, सदन को आश्वस्त करने के लिए, देश की जनता को आश्वस्त करने के लिए सदन की कोई समिति या टीम सरकार वहां भेजने का निर्णय लेगी ? यह हमने पूछा था। उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : इस पर हम विचार करेंगे।

श्री राम नरेश यादव : मंत्री जी अभी विचार करेंगे। कितनी देर लगेगी ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने कहा कि 25 हजार रुपया अभी तक दिया है। इसके पहले कभी किसी साइक्लोन में लोगों को इतनी मदद नहीं मिली . . . (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : इतनी भयंकर घटना पहले कभी नहीं हुई थी ।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: The Minister is making a statement in all responsibility. He is saying that no monies have ever been paid to the next of kin of those who died in cyclones or storms. Is that the statement of the Minister in his full responsibility? If he makes that statement, I would like to move a motion of privilege just now. I would like a proper statement from the honourable Minister.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने कहा है कि इतनी मदद मरने वालों के परिवारों को पहले कभी नहीं मिली है ।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: You have amended your statement now.

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : मैंने कहा कि इस साइक्लोन में जितने लोग मरे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, उतनी मदद कभी नहीं मिली ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The House now stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 14th May, 1990.

The House then adjourned at fifteen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Monday, the 14th May, 1990.